15th Sep,18

1. राज्यों के कमजोर कंधों पर होगा नई कृषि उपज खरीद नीति का बोझ

- किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में सरकार की ओर से नित नई पहल हो रही है, जिसमें उपज की नई खरीद नीति सबसे अहम है। लेकिन खरीद नीति की सफलता का पूरा दारोमदार राज्यों के कमजोर कंधों पर डाल दिया गया है।
- फसलों की खरीद के लिए जिन विकल्पों को रखा गया, उनमें से किसी एक को चुनने में राज्यों के पसीने छूट सकते हैं। किसानों से खरीद करने के लिए राज्यों की सरकारी मशीनरी, फौरी तौर पर फंड, गोदाम और मजबूत मंडी तंत्र की जरूरत पड़ेगी।
- अनाज, दलहन और तिलहन खरीद में राज्यों को अपने खजाने से भी मदद देनी होगी। तिलहन खरीद में काम आने वाली भावांतर भुगतान योजना में न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव के अंतर की राशि को सरकारें वहन करेंगी।
- यानी इसमें केंद्र व राज्यों की भागीदारी पचास-पचास फीसद की होगी। बाजार में तात्कालिक धनराशि के लिए राज्यों को ही रिवॉल्विंग फंड का गठन करना होगा। हालांकि बाद में केंद्र इसका समायोजन करेगा।
- खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में गेहूं व चावल की खरीद चालू होने के बाद मंडियों की हालत खराब रहती है। मंडियों का बुनियादी ढांचा चरमरा जाता है। उसी समय तिलहन व दलहन फसलों की खरीद भी होगी।
- एमएसपी का लाभ सभी किसानों को देने की सरकारी प्रतिबद्धता के चलते खरीद केंद्रों की संख्या और बढ़ानी पड़ेगी। इक्का-दुक्का राज्यों को छोड़कर बाकी जगहों पर यह करना आसान नहीं होगा। जैसे-तैसे खरीद कर भी ली गई तो खरीदे गए खाद्यान्न के भंडारण की समस्या गंभीर चुनौती बनकर उभरेगी।
- अधिकतर राज्यों की मंडियां खस्ताहाल हैं, जहां न तो शेड हैं और न ही पक्के प्लेटफार्म। इन मंडियों में उपज की क्वालिटी जांचने वाली प्रयोगशाला भी नहीं है, जहां इनका परीक्षण किया जा सके।

WWW.THECOREIAS.COM

- दलहन फसलों की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) लागू होगी, जो पूरी तरह केंद्र पोषित है। इसमें पहले से ही नैफेड जैसी सरकारी एजेंसी दालों की खरीद कर रही है। राज्य भी इसे अपनी तरह से अपना सकते हैं। वे इसकी जगह मूल्य अंतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) को भी अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस योजना में केंद्र व राज्य दोनों की हिस्सेदारी होगी। इसमें तिलहन फसलों की खरीद की जाएगी।
- तिलहन बेचने वाले किसानों को पंजीकरण पहले से ही कराना होगा। माना जा रहा है कि पीएसएस से सीमित किसानों को ही फायदा मिल सकेगा जबकि पीडीपीएस का दायरा विस्तृत होगा। इससे ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। हालांकि इस योजना की निगरानी का पुख्ता इंतजाम करना होगा।
- सरकारी खरीद में निजी क्षेत्रों का यह कोई पहला मामला नहीं है। धान की खरीद में ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले कई सालों से प्राइवेट कंपनियां खरीद कर रही हैं। हालांकि उनकी कार्य प्रणाली और उसके प्रभावों का आकलन अभी तक नहीं कराया गया है।
- तिलहन की खरीद के लिए प्रायोगिक तौर पर आठ जिलों में निजी कंपनियां खरीद करने को उतरेंगी। उनके साथ हुए करार का विस्तृत ब्यौरा बाहर नहीं आया है। मंत्रलय के एक अधिकारी ने बताया कि इसकी गाइडलाइन जल्दी ही आ जाएगी।

USE PAPER 3 AGRINOMY ,ESSAY

2. अगस्त में थोक महंगाई दर भी घटी

- खाद्य वस्तुओं की कीमत में मामूली गिरावट आने से अगस्त में थोक महंगाई दर घटकर 4.53 प्रतिशत रह गयी है। हालांकि पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि के चलते महंगाई की दर में कमी मामूली रह गई। पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि के चलते कुल महंगाई में असर को लगभग खत्म कर दिया है।
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव बढ़ने और डॉलर के मुकाबले रुपये के अवमूल्यन के चलते आने वाले दिनों में महंगाई के सिर उठाने की आशंका बरकरार है।

- वाणिज्य मंत्रलय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में थोक महंगाई दर 4.53 प्रतिशत रही जबकि जुलाई में यह 5.09 प्रतिशत थी। पिछले साल अगस्त में थोक महंगाई दर 3.24 प्रतिशत थी। थोक महंगाई का यह स्तर बीते चार महीने में न्यूनतम है। इससे पूर्व अप्रैल में 3.62 प्रतिशत थोक महंगाई दर दर्ज की गयी थी।
- इस साल अगस्त में पिछले साल के इसी माह के मुकाबले खाद्य वस्तुओं की कीमत में 4.04 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी जबकि जुलाई में यह आंकड़ा 2.16 प्रतिशत था। खासकर सब्जियों के भाव में अगस्त में 20.18 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी जबकि जुलाई में यह आंकड़ा 14.07 प्रतिशत था।
- इसी तरह दलहन की महंगाई दर में भी गिरावट दर्ज की गयी है। हालांकि आलू की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गयी है। वैसे प्याज तथा फलों की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गयी है।
- सब्जियों सहित खाद्य वस्तुओं के भाव में कमी आने का असर यह हुआ है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में वृद्धि के चलते महंगाई दर में जो वृद्धि होनी थी, वह बेअसर हो गयी है।
- थोक महंगाई दर में फ्यूल एंड पावर समूह की अगस्त में 17.73 प्रतिशत महंगाई बढ़ी है। वहीं एलपीजी की मुद्रास्फीति 46.08 प्रतिशत, डीजल की 19.90 प्रतिशत और पेट्रोल की 16.30 प्रतिशत रही है। ऐसे में अगर खाद्य वस्तुओं की कीमत में गिरावट नहीं आती तो थोक महंगाई दर बढ़ जाती।
- अगस्त में खुदरा महंगाई दर में भी गिरावट दर्ज की गयी है। इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) आगामी पांच अक्टूबर को मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगा। आरबीआइ अपनी नीति तय करते समय खुदरा महंगाई दर को ही संज्ञान में लेता है।

USE PAPER 3 ECONOMICS

3. रुपये की गिरावट असामान्य, कड़ी निगरानी जरूरी

- डॉलर के मुकाबले रुपये का सालाना चार-छह फीसद तक गिरने की उम्मीद करना स्वीकार्य है। लेकिन हालिया गिरावट इस सीमा से कहीं ज्यादा है।
- गौरतलब है कि इसी सप्ताह रुपया डॉलर के मुकाबले 72 से भी निचले स्तर तक लुढ़क गया। इस लिहाज से इस वर्ष अब तक डॉलर के मुकाबले रुपया 13 फीसद से ज्यादा लुढ़क चुका है।
- विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ : भारतीय रिजर्व बैंक) आरबीआइ (द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सात सितंबर को खत्म हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 81.95 करोड़ डॉलर गिरकर 399.282 अरब डॉलर रह गया है। इससे पहले वाले सप्ताह में भी भंडार में 1.191 अरब डॉलर की गिरावट आई थी। हालांकि बरसों तक स्थिर रहने के बाद समीक्षाधीन सप्ताह में स्वर्ण भंडार 7.19 करोड़ डॉलर बढ़कर 20.234 अरब डॉलर पर हो गया।

USE PAPER 3 ECONOMICS

4. हमसे खरीदो कच्चा तेल, अमेरिका का दांव

- अमेरिका सिर्फ भारत के लिए बेहद अत्याधुनिक हथियारों का आपूर्तिकर्ता देश बनने की ख्वाहिश नहीं रखता है बल्कि वह यह भी चाहता है कि वह भविष्य में भारत की तमाम ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करे।
- टू प्लस टू वार्ता के दौरान हुई बैठक में अमेरिकी पक्ष ने कहा कि वह भारत की कच्चे तेल व गैस की अधिकांश आवश्यकता को पूरा कर सकता है। अमेरिका लगातार कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ा रहा है और उसे भारत जैसे बड़े खरीददार की जरूरत है।
- ईरान पर लागू प्रतिबंधों पर चर्चा के दौरान भारत ने अपना पक्ष साफगोई से पेश किया। भारत ने ईरान से तेल आयात में भारी कटौती करने के रास्ते में अपनी परेशानियों के बारे में बताया। इस पर अमेरिकी अधिकारियों ने क्रूड व भारत की अन्य ऊर्जा जरूरतों के बड़े हिस्से को पूरा करने का प्रस्ताव रखा।
- क्रूड का कारोबार भारत व अमेरिका के बीच के व्यापार घाटे के संतुलन को बनाने में भी मदद कर सकता है जो अभी भारत के पक्ष में है। उक्त अधिकारी के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत अमेरिका से 2.5 अरब से 3 अरब डॉलर मूल्य का क्रूड खरीद सकता है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत ने 1.5 अरब डॉलर का क्रूड खरीदा था।
- अमेरिका के इस प्रस्ताव को भारत भी अपने लंबे समय के हितों के मुताबिक सही मान रहा है। पिछले 20-25 वर्षो में भारत खाड़ी के जिन देशों से क्रूड खरीदता है वहां लगातार कुछ न कुछ राजनीतिक या आर्थिक समस्या पैदा हो रही है। इससे क्रूड की कीमतों में भी

WWW.THECOREIAS.COM

काफी उतार चढ़ाव आता है जिसका खामियाजा भारतीय अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ता है। अगर अमेरिका से क्रूड खरीदा जाएगा तो खाड़ी क्षेत्र की अनिश्चितता से बचा जा सकेगा।

- भारत में जिस तेजी से ऊर्जा की खपत बढ़ रही है उस पर अमेरिका की नजर है। अभी भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। दूसरी तरफ वर्ष 2018 में अमेरिका ने कच्चे तेल के उत्पादन में सऊदी अरब और रूस को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में अमेरिका के तेल व गैस उत्पादन का भारत एक बड़ा बाजार बन सकता है।
- भारत ने पिछले वर्ष से अमेरिका से कच्चे तेल का आयात बढ़ा दिया है। अमेरिका के ऊर्जा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर, 2017 में भारत को 2.35 लाख बैरल प्रतिदिन क्रूड निर्यात किया गया जो जून, 2018 में बढ़कर 4.13 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है। अगस्त, 2018 में देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी इंडियन ऑयल ने अमेरिका से 60 लाख बैरल तेल खरीदने का फैसला किया है जिसकी आपूर्ति नवंबर 2018 से शुरू होगी।
- दूसरी सरकारी तेल कंपनियां भी अमेरिका के कच्चे तेलों की प्रकृति के मुताबिक अपनी रिफाइनरियों में संशोधन कर रही हैं ताकि भविष्य में ज्यादा अमेरिकी क्रूड खरीदा जा सके। भारत ने पिछले वर्ष अमेरिका से सालाना 2.2 करोड़ टन एलएनजी खरीदने का भी बड़ा समझौता किया है। **USE PAPER 2 IR /PAPER 3**

5. पारिवारिक कारोबारों की संख्या में भारत तीसरे स्थान पर

- परिवार नियंत्रित बिजनेस यानी फैमिली बिजनेस की संख्या के लिहाज से भारत दुनियाभर में तीसरे स्थान पर है। देश में परिवार-नियंत्रित कंपनियों की संख्या 111 है। इस मोर्चे पर 159 ऐसी कंपनियों के साथ चीन पहले, जबकि 121 कंपनियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका) यूएसए (दूसरे स्थान पर हैं।
- यह रिपोर्ट क्रेडिट सुइस रिसर्च इंस्टीट्यूट) सीएसआरआइ (ने तैयार की है।
- सीएसआरआइ के मुताबिक इन तीनों क्षेत्रों यानी चीन, भारत और हांगकांग गैर-जापान एशियाई क्षेत्र में परिवार नियंत्रित कारोबार में गहरी पैठ रखते हैं। गैर-जापान एशियाई क्षेत्र में स्थित फैमिली बिजनेस में इन तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी करीब 65 फीसद है। इनका कुल बाजार पूंजीकरण 2.85 लाख करोड़ डॉलर) करीब 71 फीसद (है।

WWW.THECOREIAS.COM

- सीएसआरआइ ने अपनी रिपोर्ट में गैर-जापान क्षेत्र के 11 एशियाई बाजारों को शामिल किया। दुनियाभर में परिवार नियंत्रित बिजनेस के मामले में इन बाजारों की हिस्सेदारी करीब 53 फीसद है। इन कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण चार लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा है।
- परिवार नियंत्रित बिजनेस हर क्षेत्र में अपने स्पर्धियों को मात दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवार नियंत्रित कंपनियों ने वर्ष 2006 से अब तक औसतन सालाना 13.9 फीसद प्रति शेयर का रिटर्न दिया है, जो गैर-परिवार नियंत्रित कंपनियों के मामले में महज छह फीसद रहा है।
- रिपोर्ट की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनियाभर में सबसे ज्यादा लाभकारी 50 परिवार नियंत्रित बिजनेस में से 24 एशिया से हैं। इनका कुल बाजार पूंजीकरण 748 अरब डॉलर है। इस सूची में भारतीय परिवार नियंत्रित बिजनेस की संख्या 12 है, जिनका कुल बाजार पूंजीकरण 192.2 अरब डॉलर आंका गया है।
- **PAPER 3 ECONOMICS**

6. भारत की किसान समर्थक नीति पर अमेरिका ने जताई चिंता

- अमेरिका ने आरोप लगाया है कि भारत अपने चावल और गेहूं उत्पादक किसानों को बड़ी सब्सिडी दे रहा है। ऐसा करके वह व्यापार की नीति को विकृत कर रहा है।
- भारत की इस नीति से पूरी दुनिया के चावल और गेहूं उत्पादक देश चिंतित हैं। वह भारत के घरेलू किसानों के समर्थक रवैये से परेशान हैं।
- अमेरिका का अनुमान है कि भारत अपने चावल उत्पादक किसानों को लागत में 74 से 84.2 प्रतिशत तक का सहयोग देता है। पिछले पांच साल में भारत ने 5.3 अरब डॉलर) 38 हजार करोड़ रुपये (से आठ अरब डॉलर) 57,500 करोड़ रुपये (के चावल का निर्यात किया है।

- वह चावल निर्यात करने वाला दुनिया का सबसे अग्रणी देश है, जबकि इसी दौरान भारत ने 1.9 अरब डॉलर) 13,658 करोड़ रुपये (तक गेहूं का निर्यात किया है।
- अमेरिका के कृषि कारोबार संबंधी मंत्रलय के सहायक मंत्री टेड मैकिनी ने हाल ही में भारत का दौरा कर खाद्य सुरक्षा नीति पर चर्चा की। इससे भारत से खाद्य पदार्थो का अमेरिका के लिए निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन अमेरिकी किसानों के लिए अवसर बढ़ाने के वास्ते लगातार कार्य कर रही है। इसीलिए वह अन्य देशों में कृषि उत्पादों पर दी जाने वाली सब्सिडी की समीक्षा कर रही है। **USE PAPER I SOCIETY/2 IR/ESSAY**

7. 'बढ़ते हिन्दू राष्ट्रवाद से भारत की पंथनिरपेक्ष छवि को लगा धक्का'

- हाल के दशक में भारत में हिन्दू राष्ट्रवाद एक उभरती राजनीतिक ताकत बना है। इससे देश की पंथनिरपेक्षता को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में सोशल मीडिया को इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने वाला बताया गया है।इसे स्वतंत्र विशेषज्ञ कांग्रेस सदस्यों के लिए तैयार करते हैं, जिससे उन्हें नीतियां बनाने में मदद मिले।
- 'भारत : धार्मिक आजादी के मुद्दे' शीर्षक से तैयार रिपोर्ट में धार्मिक आधार पर कथित दमन और हिंसा के विभिन्न मामलों का जिक्र किया गया है। इसमें राज्यों के स्तर पर धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून, गोरक्षा दलों, अभिव्यक्ति की आजादी पर हो रहे हमलों और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों को भारत की पंथनिरपेक्ष छवि के लिए घातक माना गया है।
- इसमें कहा गया, 'भारत के संविधान में धार्मिक आजादी को सुरक्षित किया गया है। देश की आबादी में हिन्दुओ का बहुमत है। हाल के दशकों में भारत की पंथनिरपेक्ष प्रकृति को बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए हिन्दू राष्ट्रवाद उभरती राजनीतिक ताकत बना है। इससे देश की धार्मिक आजादी पर नया खतरा पैदा हुआ है।'
- रिपोर्ट में चेताया गया है कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हिंसा की घटनाओं को बढ़ावा देने में मददगार हो रहा है। इसमें कहा गया है कि 2014 में देश में भाजपा की जीत के बाद से धार्मिक आजादी के मुद्दे की ओर ध्यान गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुर्व्यवहार की घटनाओं के चलते अमेरिका-भारत के रिश्तों में भी तनाव आया।

WWW.THECOREIAS.COM

- **USE PAPER 2 POLITY ,ESSAY**

8. भारतवंशी सांसद एच-1बी वीजाधारकों के लिए लाए बिल

- एच-1बी कर्मियों को नौकरी बदलने में सहूलियत देता है। इस बिल में अमेरिका से मास्टर्स डिग्री या उच्च शिक्षा हासिल करने वालों को जारी किए जाने वाले एच-1बी वीजा की वार्षिक सीमा 20 हजार से बढ़ाने का भी प्रावधान है। इससे ग्रीन कार्ड के लंबित आवेदनों का जल्द निपटारा हो सकेगा।
- कानून बन जाने पर एच-1बी वर्क वीजा प्रोग्राम में सुधार होने के साथ यह सरल हो जाएगा। वीजा और ग्रीन कार्ड जारी करने के शुल्क का इस्तेमाल विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) स्टेम (में निवेश बढ़ाने में किया जाएगा। अमेरिकी पेशेवरों को कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। विधेयक में अमेरिकी कर्मियों की जगह एच-1बी वीजा कर्मियों को नियुक्त करने से भी कंपिनयों को निषेध किया गया है।
- अमेरिकी में आइटी क्षेत्र से जुड़ी एक कंपनी पर अपने एच-1बी वीजा वाले कर्मियों को कम वेतन देने के कारण 45 हजार डॉलर)करीब 32 लाख रुपये (का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही कम वेतन पाने वाले 12 कर्मियों को तीन लाख डॉलर) करीब दो करोड़ रुपये (का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।
- एच-1बी वीजा के तहत अमेरिकी कंपनियां कुशल विदेशी पेशेवरों को नौकरी देती हैं। अमेरिका के लेबर वेज एंड आवर डिवीजन)डब्ल्यूएचडी (ने अपनी जांच में रेडमंड स्थित पीपल टेक ग्रुप) पीटीजी (को एच-1बी वीजा कर्मियों को उचित वेतन नहीं देने का दोषी पाया। इस कंपनी के कार्यालय बेंगलुरु और हैदराबाद में भी हैं। विभाग ने 2013 में एच-1बी वीजा नियमों का उल्लंघन कर रही 30 कंपनियों की सूची तैयार की थी। इनमें ज्यादातर कंपनियों के मालिक भारतीय-अमेरिकी हैं।

PAPER 3 ECONOMICS

9. ईरानी प्रतिबंधों का पालन नहीं करने पर अमेरिका ने

- अमेरिका ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अमेरिका उन देशों और कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को तैयार है, जो ईरान पर लगे प्रतिबंधों का पालन नहीं कर रहे।

- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गत मई में ईरान के साथ साल 2015 में हुए परमाणु समझौते से अमेरिका के हटने का एलान किया था। इसके बाद पिछले माह ईरान पर दोबारा प्रतिबंध थोप दिए गए थे। नवंबर में उस पर और प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। ट्रंप प्रशासन ईरान के तेल निर्यात पर पूरी तरह रोक लगाना चाहता है।
- भारत को कर चुका है आगाह : अमेरिका ने भारत और अन्य देशों से चार नवंबर तक ईरान से तेल आयात बंद करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। इराक और सऊदी अरब के बाद भारत के लिए ईरान तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है।

PAPER 2 IR

10. मानव विकास सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर

- यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक 2018 रिपोर्ट
- मानव विकास के मामले में भारत की स्थिति में मामूली सुधार आया है। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक पर भारत एक पायदान चढ़कर 130वें स्थान पर पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र ने मानव विकास सूचकांक पर 189 देशों की रैंकिंग की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर नार्वे तथा सबसे निचले पायदान पर अफ्रीकी देश नाइजर । वहीं भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश 136वें और पाकिस्तान 150वें स्थान पर है।

  इस रिपोर्ट में वर्ष 2017 के दौरान सभी देशों की रैंकिंग-

- ✓ प्रति व्यक्ति आय,
- ✓ जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्स्पेक्टेंसी,
- ✓ औसत स्कूली शिक्षा के आधार पर ।

- इस साल मानव विकास सूचकांक पर भारत का स्कोर 0.640 रहा है जबकि पूर्व वर्ष की रिपोर्ट में यह 0.624 था और भारत 188 देशों की सूची में 131वें स्थान पर था।
- रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से 2017 के दौरान मानव विकास सूचकांक पर भारत का स्कोर 0.427 से बढ़कर 0.640 हुआ है। इस तरह इसमें लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह इस बात का संकेत है कि देश में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।
- 1990 से 2017 की अवधि में भारत की जीवन प्रत्याशा लगभग 11 साल बढ़ी है। इसी तरह स्कूली शिक्षा के मामले में भी स्थिति सुधरी है जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय में इस अवधि में भारी भरकम 266 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- रिपोर्ट के मुताबिक 189 देशों में से 59 देश उच्च मानव विकास की श्रेणी में हैं जबकि 38 देश न्यूनतम मानव विकास की श्रेणी में आते हैं।
- रिपोर्ट में जेंडर इनइक्विलिटी इंडेक्स भी दी गई है। इस पर भारत 160 देशों की सूची में 127वें स्थान पर है। इस मामले में भी भारत ने पड़ोसी देश -बांग्लादेश और पाकिस्तान से बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में असमानता एक चुनौती है।
- **PRELIMINARY,PAPER 1 SOCIETY,PAPER3**

11. दहेज प्रताड़ना में तुरंत गिरफ्तारी संभव

- सुप्रीम कोर्ट ने दहेज कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए पिछले वर्ष जारी किए गए अपने दिशा-निर्देशों में बदलाव करते हुए दहेज उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए **परिवार कल्याण समिति गठित** करने और समिति की रिपोर्ट आने तक गिरफ्तारी न करने का निर्देश रद कर दिया है।
- दहेज उत्पीड़न के मामलों में पति और उसके परिवार वालों को तत्काल गिरफ्तारी से मिला संरक्षण समाप्त हो गया है। यानी अब अगर पुलिस को गिरफ्तारी का पर्याप्त आधार लगता है तो वह आरोपित को गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि कोर्ट ने पुलिस को सचेत किया है कि वह जरूरी और पर्याप्त आधार होने पर ही गिरफ्तारी करेगी।
- साथ ही कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए आरोपित के पास अग्रिम जमानत का विकल्प है। यहां तक कि कानून का संतुलन कायम करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया निरस्त करने का भी प्रावधान है। अदालत लगातार इस बात के लिए सजग रही है कि पीड़ित पक्ष कानून और सहानुभूति का लाभ लेकर दूसरे पक्ष को प्रताड़ित न कर पाए।

WWW.THECOREIAS.COM

- ऐसी स्थिति में विधायिका का दायित्व है कि वह इससे संरक्षण के कानून लाए और कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह उन उपायों को अच्छी तरह जांचे ताकि समाज की यह बुराई खत्म हो।
- **PAPER 1 SOCIETY**

12. गैर जमानती वारंट के आरोपितों पर सख्त चुनाव आयोग

- निर्वाचन आयोग ने अपने निर्देश में कहा है कि जल्द ही ऐसे लोगों को हिरासत में लिया जाए जो चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं।चुनाव आयोग ने पुलिस और प्रशासन को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि गैर जमानती वारंट के क्रियान्वयन में तेजी लाया जाए। मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी के दिए आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि अकेले मध्य प्रदेश में करीब 80,000 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हैं, जिन्हें पुलिस को चुनाव से पहले जेल भेजने का काम करना है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वह जेल में भी औचक निरीक्षण करे ताकि जेल के भीतर अपराधियों को मोबाइल जैसी सुविधा न मिल सके। साथ ही सभी लाइसेंसशुदा हथियारों को जमा करने के भी आयोग ने निर्देश दिए हैं।वहीं जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां आचार संहिता का ठीक से पालन हो सके, इसके लिए भी आयोग ने जिला और राज्य स्तर पर कमांड और कंट्रोल रूम बनाने का फैसला किया है। इस कंट्रोल रूम से शहर में लगे सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की गाड़ियों में लगे कैमरे की लाइव फुटेज पर निगरानी रखी जाएगी।
- चुनावी माहौल में अपराधियों से निपटने के लिए आयोग इस बार क्राइम एंड क्रिमनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। साथ ही ड्रॉप गेट्स, चेक पोस्ट और राज्यों को जोड़ने वाले नाकों पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग लगातार सभी निर्वाचन अधिकारियों, विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षकों के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है।

  आयोग का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यदि इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान, सिक्योरिटी प्लान, स्वीप प्लान और वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्लान बनाकर काम किया जाए तो नतीजे और भी बेहतर आएंगे। **USE PAPER 2 GOVERNANCE**

WWW.THECOREIAS.COM

13. पराली को संकट बनने से पहले ही निपटाने की तैयारियों में जुटी केंद्र की सरकार

- पराली से विगत वर्षो में हुई परेशानी से सबक लेते हुए सरकार ने इस साल समय रहते कमर कस ली है। इससे पहले कि जलती पराली की जहरीली हवाएं राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों को अपने आगोश में लें, केंद्र ने राज्यों को सतर्क कर दिया है।
- राज्यों को बचाव से जुड़े सभी जरूरी उपायों पर काम शुरू करने को कहा गया है। फसल कटाई का समय आमतौर पर 20 सितंबर से 15 नवंबर तक रहता है। फसल काटने के बाद खेत को खाली करने की जल्दबाजी में किसानों को पराली जलाना सबसे आसान कदम लगता है।
- वातावरण में धुआं घुलने से लोगों की सेहत पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। पहले से सतर्कता बरती जाए तो किसान पराली को जलाने के अलावा दूसरे विकल्प भी अपना सकते हैं। सरकार की ओर से किसानों को पराली को जलाने के अलावा दूसरे तरीकों से नष्ट करने के उपायों के लिए काफी मदद दी गई है।
- किसानों को जागरूक करने और मशीनी उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। इसके तहत राज्यों में सोशल मीडिया और दूसरे प्रचार माध्यमों के जरिये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पंजाब जैसे राज्यों में इसे लेकर जागरूकता फैलाने वाले गाने भी तैयार किए गए हैं।
- PAPER 2/3

14. रेलवे की सिगनल प्रणाली बदलना तय निजी कंपनियों को भी मिलेगा मौका

- सिगनल प्रणाली के आधुनिकीकरण के रेलवे के प्रस्ताव को कुछ संशोधन के साथ इस संबंध में कैबिनेट नोट तैयार हो रहा है, जिसे शीघ्र ही मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। संशोधित प्रस्ताव के तहत विदेशी कंपनियों के अलावा देश की सार्वजनिक व निजी दोनों तरह की कंपनियों को सिगनल प्रणाली के उन्नयन का मौका दिया जाएगा।
- मौजूदा सिगनल प्रणाली ट्रेनों की रफ्तार में बाधक होने के साथ-साथ ट्रेनों की लेटलतीफी और हादसों के लिए जिम्मेदार है। इसलिए इसके स्थान पर हमें अत्याधुनिक यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम-2 सिगनल प्रणाली को अपनाना चाहिए।

- यह प्रणाली तीनों समस्याओं से एक साथ निजात दिलाने में सक्षम है। इस संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र की दो कंपनियों -पावरग्रिड और रेलटेल के अलावा कुछ बड़ी विदेशी कंपनियों का नाम सुझाया था। यदि इन कंपनियों को अनुबंध दिए जाएं तो रेलवे को काफी बचत हो सकती है।
- संशोधित प्रस्ताव के तहत नई सिगनल प्रणाली होगी तो यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम-2 की तर्ज पर ही। लेकिन उसके कार्यान्वयन में विदेशी कंपनियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र ही नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र की देशी कंपनियों को भी मौका दिया जाएगा।

- क्या है यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम-2
- यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम-2 में ट्रेनों का संचालन लंबे ब्लॉकों के बजाय छोटे ब्लॉकों पर किया जाता है। जिससे दो ट्रेनों के बीच मात्र 500 मीटर के अंतराल की जरूरत पड़ती है। इससे किसी रूट पर एक ट्रेन के प्रस्थान के एक मिनट बाद ही दूसरी ट्रेन रवाना की जा सकती है। मौजूदा ऑटोमैटिक सिगनल प्रणाली में दो ट्रेनों के बीच कम से कम दस मिनट अथवा बीस किलोमीटर का अंतराल रखना पड़ता है।
- **USE PAPER 3**

15. भारत की रूस को भी साधने की कोशिश

- अमेरिका के साथ बेहद अहम वार्ता संपन्न होने के बाद भारत रूस के साथ अपने रिश्तों को भी तराशने में जुट गया है। इस क्रम में रूस की दो दिवसीय यात्र पर पहुंचीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अक्टूबर, 2018 में दोनों देशों के बीच होने वाली शीर्षस्तरीय सालाना बैठक को लेकर अहम बातचीत की। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन की अगुआई में होगी।
- दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में कारोबारी रिश्तों में काफी बेहतरी को देखते माना जा रहा है कि मोदी व पुतिन के बीच होने वाली बैठक में भी आर्थिक रिश्तों पर खास जोर दिया जाएगा। स्वराज ने रूस में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इसके बाद स्वराज और रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरीसोव के साथ व्यापार, अर्थ, विज्ञान व तकनीकी पर आयोग की बैठक हुई।
- वर्ष 2017 में दोनों देशों की कंपनियों ने एक-दूसरे के यहां 30 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया था। जबकि यह लक्ष्य वर्ष 2025 तक के लिए रखा गया था। अब स्वराज ने प्रस्ताव किया है कि वर्ष 2025 तक द्विपक्षीय निवेश का लक्ष्य बढ़ाकर 50 अरब डॉलर कर देना चाहिए। संभवत अगले महीने मोदी व पुतिन के बीच वार्ता में इस संदर्भ में घोषणा की जाएगी।

WWW.THECOREIAS.COM

- **USE PAPER 2 IR**

16. प्रत्येक सप्ताह जांचें गंगाजल और दें रिपोर्ट :एनजीटी

- कुंभ स्नान को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) एनजीटी (ने तेवर और सख्त किए हैं। गंगा में किसी प्रकार का प्रदूषित पानी जाने से रोकने के साथ गंगा जल की हर सप्ताह जांच कराने के आदेश उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड) यूपीपीसीबी (को दिए हैं।
- टिब्यूनल ने साफ किया है कि गंगा किनारे के सभी जिलों में प्रदूषण विभाग द्वारा नदी के पानी की समय-समय पर जांच हो और इसकी रिपोर्ट बनाकर भेजी जाए। यह प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से शुरू होगी और कुंभ के समापन तक चलेगी। निर्देश हैं कि लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी पर कार्रवाई भी की जाए।
- एनजीटी ने यूपीपीसीबी से कहा है कि वह जिला प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दें कि गंगा के पानी की हर हफ्ते जांच कर जरूरी कदम उठाए। साथ ही रिपोर्ट तत्काल भेजी जाए। इसमें लापरवाही करने वाले के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो।
- साथ ही प्रदूषित पानी खुले नालों में न बहाया जा सके, इस पर सख्ती से अमल किया जाएगा।
- **USE PAPER 3 ENVIRONMENT**

17. हॉवित्जर तोप 'के-9 वज्र-टी' ने 50 किमी दूर भेदा लक्ष्य

- भारतीय सेना ने जोधपुर के पोखरण फायरिंग रेंज में देश में निर्मित हॉवित्जर तोप के-9 वज्र-टी की लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता का परीक्षण किया। पिछले परीक्षण के बाद इसमें 13 सुधार किए गए हैं। 40 से 50 किमी रेंज वाली इस तोप से छह गोले दागे गए। सभी गोलों ने अपने लक्ष्य पर अचूक प्रहार करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया।

- मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत वज्र को निजी क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने बनाया है। सेना ने 155 एमएम की इस हॉवित्जर तोप के पिछले परीक्षण के दौरान कुछ सुधार करने को कहा था। सुधार के बाद एडवांस्ड तोप का पोखरण फायरिंग रेंज में सेना ने एक बार फिर से परीक्षण किया।
- यह तोप खास तौर से रेगिस्तान की परिस्थियों को ध्यान में रखकर विकसित की गई है। अगले कुछ दिनों में इसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा। तोप को पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाएगा।
- लार्सन एंड टूब्रो ने दक्षिण कोरिया की कंपनी टेकविन के साथ मिलकर इस तोप का निर्माण किया है। गुजरात के हजीरा में इसका कारखाना स्थापित किया गया है। तोप में 50 प्रतिशत सामग्री देश में ही निर्मित की गई है। सेना ने साढ़े चार हजार करोड़ में 100 तोपों का ऑर्डर दिया है।
- **PRELIMINARY & PAPER 3 SCIENCE & TECH**

18. छग के नक्सल इलाकों के विकास को केंद्र से 200 करोड़ मिलेंगे सालाना

- छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों के विकास के लिए केंद्र सरकार अब सालाना करीब दो सौ करोड़ रुपये और देगी।
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई) जिलों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने सालाना एक हजार करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार यह राशि देश भर के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित 35 जिलों के विकास के लिए देगी।
- छत्तीसगढ़ के 14 में से आठ जिलों को बेहद संवेदनशील जिलों में शामिल किया गया है। इनमें बस्तर के सातों जिले-बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर के साथ ही राजनांदगांव जिले को भी शामिल किया गया है।
- केंद्र सरकार ने इस साल देश के 20 जिलों को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत ऑपरेशन प्रहार का दायरा बढ़ाने की योजना है।
- केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित राज्यों को अर्धसैनिक बल, युद्ध के साजोसामान, हेलीकॉप्टर, बम निरोधक दस्ते आदि तो दे ही रही है, साथ ही ऐसे इलाकों के विकास पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। इन इलाकों में सड़क और संचार तंत्र के विकास पर जोर है।
- बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में 1200 किमी से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। संचार तंत्र को मजबूत करने के लिए समूचे बस्तर में मोबाइल नेटवर्क बिछाने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। इसके लिए भारत नेट की तर्ज पर बस्तर नेट परियोजना चलाई जा रही है। नक्सल इलाकों में स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा आदि पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
- **USE PAPER 3 INTERNALSECURITY**

WWW.THECOREIAS.COM

19. छत्तीसगढ़ के गंगरेल में बनेगा देश का पहला कृत्रिम बीच : अल्फोंस

- इसके लिए तकनीकी व वित्तीय मदद पर्यटन मंत्रलय वहन करेगा। वैश्विक स्तर पर पर्यटकों की आवक में पिछले वर्ष भारत में दर्ज संख्या में 14 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। तीन वर्ष में पर्यटकों की संख्या दो गुना करने का लक्ष्य निर्धारित है।
- विदेशी पर्यटकों से इस वर्ष एक लाख 77 हजार करोड़ की आय हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20 फीसद अधिक है। पर्यटन मंत्रलय ने धार्मिक आस्था के केंद्रों को विकसित करने के लिए प्रसाद योजना की शुरुआत की है, जिसमें छत्तीसगढ़ का एक प्रोजेक्ट शामिल है।
- **PRELIMINARY**

20. भारत और अमेरिका के फौजियों का साझा सैन्य अभ्यास

- भारत व अमेरिका के बीच 'संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास-2018' की तैयारी पूरी कर ली गई है। अमेरिकी सैन्य टुकड़ी चाकचौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच चौबटिया छावनी क्षेत्र में पहुंच गई है।
- 16 सितंबर से 'काउंटर इंसर्जेसी एवं काउंटर आतंकवाद' थीम पर भारत व अमेरिकी सेना का 14वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू होगा।
- रक्षा सहयोग एवं सामरिक संबंधों को और मजबूती देने के मकसद से भारत व अमेरिका के बीच इस 'संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास' को बेहद अहम माना जा रहा है।

- 29 सितंबर तक चलने वाले युद्धाभ्यास में खासतौर पर आतंकवाद के खात्मे तथा आंतरिक सुरक्षा आदि पहलुओं से जुड़े 'काउंटर इंसर्जेसी एवं काउंटर आतंकवाद' के तहत इंडो अमेरिकन सेना के जांबाज रणकौशल का प्रदर्शन करेंगे।
- **USE PAPER 2 IR**

21. गूगल का मेलिंग एप इनबॉक्स अगले साल मार्च में होगा बंद

- गूगल अपने अल्टरनेट मेलिंग एप इनबॉक्स को अगले साल मार्च से बंद कर देगा। तब तक यूजर्स अपने पारंपरिक जीमेल एप पर शिफ्ट हो सकेंगे। यह जानकारी कंपनी ने अपने ब्लाग में दी है।
- वर्ष 2014 में इनबॉक्स लांच किया गया था। इसे जीमेल के साथ इनोवेटिव न्यू ईमेल एप के रूप में पेश किया गया था। इसके माध्यम से गूगल नए मेलिंग फीचर की टेस्टिंग कर रहा था, जिसे बाद में जीमेल में शामिल किया जा सकता था।
- PRELIMINARY

EDITORIAL

1. जल संकट और बाढ़ का समाधान

- जलवायु परिवर्तन व जल संकट का दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था पर संभावित असर के संबंध में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में देशों के आर्थिक विकास थमने की आशंका जताई गई है। ऐसे में समय रहते यदि इस समस्या का समाधान तलाशते हुए उसे लागू नहीं किया गया तो भारत में भी भीषण जल संकट पैदा हो सकता है। भारत में इस समस्या के समाधान के तौर पर योजनाएं तो काफी बनाई गई हैं, लेकिन अब तक उसे समुचित तरीके से कार्यान्वित नहीं किया गया है।
- विश्व बैंक की जलवायु परिवर्तन, जल एवं अर्थव्यवस्था पर एक रिपोर्ट 'हाइ एंड ड्राइ क्लाइमेट चेंज, वाटर एंड द इकोनोमी' के अनुसार जल संकट के कारण अधिकांश देशों के आर्थिक विकास की गति थम सकती है। साथ ही इससे लोगों के विस्थापित होने की दर में वृद्धि हो सकती है।
- इस समस्या की चपेट में तकरीबन पूरी दुनिया के आने की आशंका जताई गई है। दरअसल जलवायु परिवर्तन से जल संकट बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या, लोगों की बढ़ती आमदनी और शहरों के विस्तार से पानी की मांग में भारी बढ़ोतरी होने वाली है, जबकि जल आपूर्ति की कोई ठोस व्यवस्था कहीं नहीं है। भारत के संदर्भ में इस रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि यहां भी लोगों को पानी की भीषण किल्लत का सामना करना पड़ेगा। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भारत में औसत से कम बारिश होने पर संपत्ति से जुड़े झगड़ों में हर साल अमूमन चार प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है। कई मामलों में देखा गया है कि बाढ़ आने पर दंगे भी होते हैं।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि गुजरात में जब जमीन के नीचे पानी का स्तर गिरने से सिंचाई की जरूरतों के लिए पानी को हासिल करना महंगा हो जाएगा तो किसान फसल प्रणाली में बदलाव करने के बजाय या फिर पानी के बेहतर उपयोग का रास्ता अपनाने के बजाय शहरों की ओर पलायन कर सकते हैं। भूमिगत जल की पंपिंग का भारत के कुल कार्बन उत्सर्जन में चार से छह प्रतिशत तक का योगदान है। जल संकट आर्थिक वृद्धि और विश्व की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है और जलवायु परिवर्तन इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है।
- जल-संसाधन का बेहतर प्रबंधन नहीं करने पर विशाल आबादी वाले देशों में आर्थिक वृद्धि में व्यवधान पैदा हो सकता है। इसलिए सभी देशों को पानी के दीर्घकालिक प्रबंधन हेतु ठोस नीति बनानी होगी और उसे लागू करना होगा। विश्व बैंक के अनुसार मानसून के संबंध में अनुमानों में एकरूपता नहीं है। भारत में जलसंकट की व्यापकता के बारे में जानकार अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि भारत की स्थिति दयनीय रहेगी। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का मिजाज पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा।
- बहरहाल जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आदि के कारण सभी देशों में पानी की मांग बढ़ेगी।
- भारत का मौसम विविधतापूर्ण है, जिसमें उतार-चढ़ाव की स्थिति लगातार बनी रहती है। यहां के किसी भी प्रदेश में गर्मी के दिनों में सूखा पड़ सकता है तो बारिश के मौसम में बाढ़ आ सकती है। दोनों ही अवस्था में व्यापक पैमाने पर जान-माल की क्षति का होना निश्चित है।

WWW.THECOREIAS.COM

- हालांकि इस दिशा में नदियों को आपस में जोड़कर इस तरह की आपदा से जरूर निजात पाई जा सकती है। इसकी मदद से देश के तकरीबन सभी खेतों तक पानी पहुंचाया जा सकता है, जिससे खाद्यान्न संकट जैसी बड़ी समस्या का समाधान भी किया जा सकता है। इससे बिजली की कमी भी दूर की जा सकती है।
- चीन ने भी नदियों को आपस में जोड़ने की अहमियत को समझा है। चीन की नदियों को नहरों के माध्यम से जोड़ने की परिकल्पना लगभग पांच दशक पुरानी है, लेकिन ऐसी परियोजना की सफलता के प्रति आशंका की वजह से इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका था। बाढ़ एवं सूखे की मार से बेदम होकर चीन ने आखिरकार इस दिशा में आगे जाने का निर्णय लिया।
- भारत में नदियों को जोड़ने की दिशा में लंबे समय से काम हो रहा है। बिहार में कई नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के पूरा होने पर इस राज्य के कई जिलों को बाढ़ और सूखे से निजात मिल सकेगी। साथ ही इससे ढाई लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई भी हो सकेगी।
- पांच दशक पूर्व का प्रस्ताव : भारत में सबसे पहले 1972 में 2,640 किलोमीटर लंबे नहर के माध्यम से गंगा और कावेरी को जोड़ने का प्रस्ताव तत्कालीन सिंचाई मंत्री के एल राव ने रखा था।
- इस प्रस्ताव के आलोक में 1974 में डी जे दस्तूर गारलेंड नहर परियोजना लेकर सामने आए, लेकिन हमारे देश में नदियों को जोड़ने की दिशा में पहल सबसे पहले आर्थर कॉटन ने की थी।
- बीसवीं शताब्दी के आरंभिक चरण में आर्थर कॉटन देश में बहने वाली सभी नदियों को आपस में जोड़ना चाहते थे, लेकिन उनका मकसद कृषि क्षेत्र को विकसित करना या प्रदेशों को बाढ़ और सूखेकी समस्या से छुटकारा दिलाना नहीं था। वे इस तरह की परियोजनाओं को पूरा करने के जरिये भारत पर ब्रिटिश राज की पकड़ को मजबूत बनाना चाहते थे।
- नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी- इसी क्रम में 1982 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी (एनडब्लूडीए) का गठन किया गया, जिसका काम था प्रस्तावित परियोजनाओं की सफलता से जुड़ी संभावनाओं को तलाशना एवं उसे अमलीजामा पहनाना।
- एक परियोजना के अंतर्गत हिमालय से निकलने वाली उत्तर भारत और दक्षिण भारत की पेनिनसुलर नदियों को आपस में नहर के माध्यम से जोड़ना था। इस आलोक में उत्तरी भारत में बांधों एवं नहरों की श्रृंखला के द्वारा गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी आदि की सहायता से प्रारंभिक चरण में 2,20,000 वर्ग किलोमीटर में सिंचाई एवं 30 गीगावॉट बिजली उत्पादन करने जैसे कार्यों को मूर्त रूप देने की परिकल्पना की गई।

WWW.THECOREIAS.COM

- दक्षिण भारत की पेनिनसुलर नदियों में महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि को जोड़ने की बात कही गई।
- दूसरे चरण में पश्चिम दिशा में मुंबई की तरफ बहने वाली नदियों और दक्षिण दिशा में तापी नदी को जोड़ने का प्रस्ताव था।
- तीसरे चरण में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी उपलब्ध करवाने हेतु केन एवं चंबल नदी को जोड़ने की परिकल्पना की गई। पुन: पश्चिम दिशा की तरफ पश्चिमी घाट के किनारे से बहती हुई अरब सागर में मिलने वाली नदियों का मार्ग बदल कर 1,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिंचाई करने एवं चार गीगावॉट बिजली उत्पादन करने की योजना बनाई गई। पैसे की कमी, पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं, भूमि प्रयोग और क्षेत्रीय पर्यावरण में होनेवाले संभावित बदलाव, कृषि पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव, बड़ी संख्या में संभावित विस्थापन की आशंका, भूमि अधिग्रहण आदि समस्याओं के कारण नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया।
- अटल सरकार की अहम भूमिका : नदियों को आपस में जोड़ने से पूरे देश में व्याप्त जल संकट और बाढ़ की समस्या से छुटकारा पाने के लिए नदी जोड़ने कि परियोजना को काफी महत्वपूर्ण माना। अपनी इस महत्वाकांक्षी परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए वाजपेयी ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था। इस टास्क फोर्स के मुताबिक सभी नदियों को आपस में जोड़ने के बाद 160 मिलियन हेक्टेयर भूमि की अतिरिक्त सिंचाई की संभावना 2050 तक बढ़ जाएगी, जबकि सामान्य परिस्थिति में उक्त अवधि में महज 140 मिलियन हेक्टेयर भूमि की ही सिंचाई की जा सकती है।
- मध्य प्रदेश से हुई शुरुआत- नदियों को आपस में जोड़ने वाली देश की प्रथम परियोजना का उद्घाटन नवंबर, 2012 में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के क्षिप्रा टेकरी में किया गया। इस परियोजना के तहत नर्मदा और क्षिप्रा को आपस में जोड़ना था, ताकि क्षिप्रा नदी का पुनरुद्धार किया जा सके।

- 21वीं सदी के आरंभिक चरण में गंगा को ब्रह्मपुत्र से, गंगा को पुन: महानदी एवं गोदावरी से, गोदावरी को कृष्णा, पेन्नार तथा कावेरी से, नर्मदा को तापी से एवं यमुना को साबरमती से जोड़ने की योजना थी।
- महाराष्ट्र और गुजरात के बीच दमन, गंगा एवं पिंजाल को भी आपस में जोड़ने का प्रस्ताव था।

USE ESSAY & PAPER 1 GEOGRAPHY

2. अदूरदर्शी नेतृत्व के दुष्परिणाम

- चाबहार बंदरगाह का संचालन एक माह के भीतर भारतीय कंपनी के हाथ आने की खबरों के बीच एक खबर यह भी है कि अमेरिका इसकी समीक्षा कर रहा है कि इस परियोजना से अफगानिस्तान के कौन-कौन हित पूरे होंगे? पता नहीं उसकी समीक्षा का निष्कर्ष क्या हो, लेकिन यह जानना जरूरी है कि आज हमें बहार, ईरान से होते हुए काबुल का रास्ता तय करना पड़ रहा है तो अपनी भूलों के कारण।
- जब दिसंबर 1839 में जनरल जोरावर सिंह ने सदियों के भटकाव के बाद उत्तरी कश्मीर के पर्वतीय राज्य गिलगित बाल्टिस्तान को डोगरा शासन में शामिल किया था तो ताशकंद, काबुल, काशगर और चीनी नगरों से व्यापार का पुराना सिल्क रोड फिर खुल गया था।
- 16 नवंबर, 1947 को हमने इसे पाकिस्तान चले जाने दिया। फिर काबुल, अफगानिस्तान का यह रास्ता स्थाई रूप से बंद हो गया और आज हमें बहार से काबुल का रास्ता तय करना पड़ रहा है।
- गिलगित-स्कदरू का यह क्षेत्र ब्राहमी लिपि में लिखे संस्कृत के शिलालेखों से भरा हुआ है। बौद्ध धर्म से प्रभावित यह क्षेत्र चीनी तीर्थयात्रियों के भारत में आगमन का मार्ग भी रहा है।
- आशा है कि भारत-अमेरिका टू प्लस टू वार्ता के दौरान ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास एवं संलन का भारतीय पक्ष अमेरिकी मंत्रियों ने समझा होगा। इस रणनीतिक पहल की प्रत्येक दशा में रक्षा की जानी हिए। चाबहार का सफल संचालन भारत, अफगानिस्तान ही नहीं, बल्कि अमेरिकी रणनीतिक लक्ष्यों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
- अगर 1947 में हमें राष्ट्रीय हितों की सही समझ होती तो श्रीनगर से काबुल का रास्ता तय करना आज कुछ घंटों की बात होती। आधा-अधूरा कश्मीर आज हमारे लिए राष्ट्रीय समस्या बना है। उस काल की भूलों की जो लंबी सूची है उसमें कश्मीर सबसे ऊपर है। लगता है कि हमारे नेतृत्व को युद्धों, रणनीतियों, रक्षा दायित्वों की समझ नहीं थी। तब सैनिकों को मकान आदि बनाने जैसे कार्यों में भी लगाया गया था। माउंटबेटन से सहयोग लेना गलत नहीं था, लेकिन वह मूलत :ब्रिटिश, अमेरिकी रणनीतिक हितों के रक्षक थे।
- गिलगित बाल्टिस्तान का भू-राजनीतिक महत्व आज स्पष्ट हो रहा है। हमारी 70 किमी लंबी सीमाएं अफगानिस्तान के सबसे अविकसित क्षेत्र वाखान गलियारे से मिलती हैं। यह अफगानिस्तान को चीन से जोड़ता है। इसके दक्षिण में पाक अधिकृत कश्मीर में चीन हाईवे बना रहा है।
- 1947 युद्ध के दौरान स्कदरू गिलगित में सिर्फ सेनाओं को पहुंने की जरूरत थी, या तो सड़क से या पैराड्रॉपिंग के जरिये। अगर कोई भारतीय सेनाध्यक्ष रहा होता तो तत्काल सोचता, लेकिन सक्रिय युद्ध के दौरान यहां ब्रिटिश सेनाध्यक्ष थे।
- आज अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों से संपर्क के लिए हमें ईरान के बहार बंदरगाह के रूप में विकल्प की तलाश है, लेकिन अपना रास्ता जो श्रीनगर-स्कदरू-गिलगित से होता हुआ काराकोरम पर्वतमाला के इरशद र्दे से गुजरता हुआ अफगानिस्तान के वाखान गलियारे तक था, उसे गंवा दिया गया। यह न किया गया होता आज गिलगित-श्रीनगर अफगानिस्तान, मध्य एशिया से भारत के व्यापार का बड़ा केंद्र होता।
- अंग्रेज अपने भारतीय साम्राज्य के हित को बखूबी समझते थे। उन्होंने ही गिलगित एजेंसी का गठन किया था। शायद माउंटबेटन को उम्मीद न रही होगी कि भारतीय सेनाएं कबाइलियों की कमर तोड़ते हुए इतनी जल्दी उड़ी पहुंच जाएंगी और मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ने लगेंगी। उनका आगे बढ़ना रोककर उड़ी में ही कैंप करा दिया गया। क्यों? क्या नेतृत्व की सोच यह थी कि कुछ कश्मीर पाकिस्तान के पास भी रह जाए? उड़ी में सेनाओं को रोक कर हमने खुद ही कश्मीर समस्या पैदा होने दी। गिलगित-बाल्टिस्तान को नियंत्रण में लेने का कोई प्रयास ही नहीं किया, जबकि हमारे पास तीन लाख की सक्रिय सेना थी। कश्मीर की बंदरबांट का इंतजाम

WWW.THECOREIAS.COM

करते हुए एक जनवरी, 1949 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा युद्धविराम घोषित करा दिया गया। इसके बाद वार्ताओं का निर्थक सिलसिला चला।

- उस समय चीन में गृहयुद्ध चल ही रहा था। हमारे यहां युद्ध विराम के नौ महीने बाद एक अक्टूबर 1949 को माओ गृहयुद्ध में विजय के बाद सत्ता में आए और एक वर्ष में ही हमारे क्षेत्र अक्साई चिन के एक पुराने व्यापारिक मार्ग से होकर 6 अक्टूबर, 1950 को तिब्बत पर हमला कर वहां अपना आधिपत्य कायम कर लिया। पता नहीं क्यों हमने अलसल्वाडोर के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में तिब्बत की आजादी का प्रकरण उठने ही नहीं दिया। उसी महीने कोरिया युद्ध में भी चीन ने अपनी सेनाएं भेजीं।
- माओ के सामने चीन के पुनर्निर्माण का बड़ा लक्ष्य था, लेकिन उनने अपने राष्ट्रीय हित के कार्यो में विलंब नहीं किया। उन्होंने अक्साई चिन की एक सड़क पर काम शुरू करा दिया। 1957 में जब हमारे इलाके में बनी वह सड़क पूरी हुई और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में यह खबर छपी तब हम यह तथ्य जान पाए।
- इसके बाद जून 1958 में विदेश सचिव सुविमल दत्त और सेनाध्यक्ष जनरल थिमैया की मौजूदगी में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में यह कहा जा रहा था कि अक्साई चिन रोड हमारे क्षेत्र से गुजरती है या नहीं, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण ही नहीं है। आजादी के 11 साल हो गए थे और हमारा यह हाल था। जबकि वह सड़क भारतीय क्षेत्र में लगभग 50 किमी अंदर स्थित अक्साई चिन झील के दक्षिण से गुजरती है। क्या यह नहीं लगता कि हमने अपनी सरहदों और अपनी सुरक्षा से मजाक किया?
- हमारे नेतृत्व को यह जानना हिए था कि हमारी सीमाएं कहां से गुजरती हैं। अपनी सीमाओं तक पहुंचना उनकी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन उस काल में नकली विचारधाराओं के ढकोसले बहुत भारी थे। किसी ने सोचा ही नहीं कि अफगानिस्तान के साथ लगती सीमाएं हमारे नियंत्रण में हर हाल में होनी चाहिए। यह अफसोस की बात है कि तत्कालीन नेतृत्व में रणनीतिक समझवाला कोई था ही नहीं। जब सेना को गरम कपड़ों की जरूरत थी तो एक मंत्री जी ऐसे आए जिन्होंने खादी के कपड़े खरीदवा डाले।
- भू-राजनीतिक मानचित्र पर पाकिस्तान एक बहुत बड़ी दीवार की मानिंद है जिसने मध्य एवं पश्चिम एशिया की ओर भारत का रास्ता रोक रखा है। वाखान गलियारा उस दीवार में एक सुरंग की तरह हो सकता था। अगर गिलगित-बाल्टिस्तान हमारे पास होता तो पाकिस्तान हमारे लिए कोई खतरा बन ही नहीं पाता। अफगानिस्तान हमारा महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी होता। उन पर्वतों और घाटियों के रास्ते काबुल हमें आमंत्रित कर रहा होता। आज उसी इलाके के पहाड़ों को चीरते हुए चीन द्वारा जो महत्वाकांक्षी कॉरिडोर-सीपैक बनाया जा रहा है उसकी कल्पना भी न हो पाती। काबुल, कांधार, ताशकंद, काशगर हमारे बहुत निकट होते। यह सड़क एक महान संभावना थी जो नेतृत्व की घोर अदूरदर्शिता के कारण संभव न हो सकी। **USE PAPER 2 IR/ESSAY**

WWW.THECOREIAS.COM

3. नदी जोड़ना कितना व्यावहारिक

- सर्वोच्च न्यायालय नदियों को आपस में जोड़ने के मुद्दे पर अपनी नाराजगी जता चुका है। शीर्ष अदालत का मानना है कि इस तरह की कोई भी योजना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि इस तरह की परियोजनाओं को पूरा करने में समय-सीमा का ध्यान नहीं रखा जाता है।
- इससे परियोजना की लागत में मुद्रास्फीति एवं दूसरे कारणों से बेहिसाब इजाफा होता है व उक्त परियोजना का पूरा होना असंभव हो जाता है।
- दूसरे पहलुओं पर गौर करें तो इस तरह की परियोजनाओं के लिए जमीन की काफी आवश्यकता होती है और भूमि अधिग्रहण आज भी एक गंभीर मसला है, जिसका समाधान आसान नहीं है। इस क्रम में बड़े स्तर पर विस्थापन की जरूरत होती है। विस्थापन और पुनर्वास दोनों पेचीदा मामला है, जिसका समाधान आसान नहीं है।
- इस संबंध में पर्यावरण में होने वाले आमूल-चूल परिवर्तन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता और आज पर्यावरण और लोक कल्याण ऐसे मसले हैं, जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। इसलिए नदियों को जोड़ने से संबंधित परियोजना का विवादस्पद होना लाजिमी है।
- भले ही नदियों को जोड़ने की संकल्पना को साकार करना आसान नहीं है, लेकिन सूखा और बाढ़, इन दोनों ही समस्या के समाधन के तौर पर यह सर्वाधिक बेहतर विकल्प है। चीन ने इस दिशा में व्यापक कामयाबी हासिल की है। वहां पर पर्यावरण, विस्थापन एवं भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों को सुलझाया गया है।

- मौजूदा समय में जलसंकट, बाढ़, सूखा आदि समस्याओं से निपटने के लिए इस तरह की परियोजनाओं को भारत में लागू करना अति आवश्यक है, क्योंकि आपदाओं से होने वाला आर्थिक नुकसान एवं जान-माल की क्षति नदियों को जोड़ने में होने वाले खर्च एवं विस्थापितों के दुख-दर्द से अधिक है। अगर नदियों को आपस में जोड़ा जाता है तो इससे पानी की कमी और बाढ़ की समस्या दोनों से निजात पाया जा सकता है। साथ ही इससे अनाज का उत्पादन भी बढ़ेगा। **USE PAPER 1/ESSAY**

4. स्वच्छता के लिए सोच बदलें

- स्वच्छ वातावरण ही मानव जीवन को सुविधाजनक और सम्मान से जीने लायक बनाता है। स्वच्छता शरीर को ही स्वस्थ नहीं रखती, सोच को भी बेहतर बनाती है। यदि हमारे आसपास साफ-सुथरा माहौल हो तो वहां सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है और ऐसी ऊर्जा कार्य संस्कृति को बेहतर बनाती है।
- हमारे सभी सार्वजनिक स्थल स्वच्छ हों तो दुनिया में हम एक स्वच्छ देश के तौर पर जाने जाएंगे और यदि एक बार स्वच्छ देश के रूप में भारत की पहचान स्थापित हो जाए तो विदेशी पर्यटक खिंचे चले आएंगे। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और इससे सभी लाभान्वित होंगे।

- स्वच्छता अभियान को सरकार के स्तर पर तो बढ़ावा दिया ही जा रहा है, बहुत-सी गैर सरकारी संस्थाएं भी इसमें अपना योगदान दे रही हैं, लेकिन जरूरत इसे जन आंदोलन बनाने की है। हर किसी के मन में खुद से ही यह भावना पैदा होनी चाहिए कि अपने आसपास सफाई कैसे रखी जाए? हर चीज अकेले सरकार नहीं कर सकती।
- दुनिया के साफ-सुथरे माने जाने वाले देशों का अनुभव यही कहता है कि स्वच्छता के मामले में जन सहयोग आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। जन-जन के मन में इस भावना को जागृत करने के लिए हर स्तर पर हर संभव उपाय करने होंगे। प्रशासन और राजनीति के स्तर पर आदर्श प्रस्तुत किए जाएं तो यह सोने पर सुहागा होगा।
- नियम-कानूनों का सही पालन किस तरह साफ-सफाई के मामले में प्रभावी साबित होता है, इसका पता देश की राजधानी में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के इलाके को देखने से चलता है। इस इलाके में आप नई जमीन नहीं ले सकते और नया मकान भी बना नहीं सकते। ऐसे में यहां पर आबादी का घनत्व नियंत्रण में रहता है।

WWW.THECOREIAS.COM

- चूंकि ऐसे इलाकों में अनधिकृत कालोनी नहीं बसने दी जाती और अवैध निर्माण भी नहीं होने दिए जाते इसलिए ट्रैफिक जाम, गंदगी के साथ वायु प्रदूषण की समस्या भी काबू में रहती है।
- आज देश के महानगरों की एक बड़ी समस्या आबादी का घनत्व बढ़ना है। नियम-कानूनों की अनदेखी से महानगरों और अब तो नगरों में भी जगह-जगह अनधिकृत तौर पर कालोनियां बस जाती हैं। फिर राजनीतिक लाभ की दृष्टि से उन्हें नियमित कर दिया जाता है।
- बीते दिनों दिल्ली में लैंड पूलिंग नीति के तहत करीब 17 लाख मकान बनाने का रास्ता साफ कर दिया गया। इसका मतलब है कि अगले कुछ सालों में दिल्ली में करीब एक करोड़ आबादी और बढ़ जाएगी। किसी भी शहर में नई आबादी के रहने के लिए मकान बनना-बनाना ही पर्याप्त नहीं होता।
- परिवहन, सुरक्षा, सफाई सरीखी बुनियादी सुविधाओं का ढांचा भी चाहिए होता है। यदि इस बुनियादी ढांचे की चिंता नहीं की जाएगी तो स्वच्छता अभियान को साकार करना मुश्किल होगा।
- यह सही है कि स्वच्छता अभियान के चलते लोगों में साफ-सफाई को लेकर जागरूकता आई है और जहां स्थानीय प्रशासन ने सफाई को लेकर सक्रियता दिखाई है वहां माहौल बदला है और सार्वजनिक स्थल पहले की तुलना में साफ-सुथरे दिखने शुरू हुए हैं, जैसे कि इंदौर। लचर सफाई व्यवस्था के लिए एक नहीं, बल्कि कई कारण जिम्मेदार होते हैं। इन कारणों के लिए राज्य सरकारें और साथ ही संबंधित सरकारी विभाग कसूरवार हैं।
- यह देखने में आता है कि शहरों में साफ-सफाई की योजनाएं नियमित कालोनियों के लिए तो बनती हैं, लेकिन अनियोजित कालोनियों के लिए मुश्किल से ही बनती हैं, जबकि एक बड़ी मात्र में कूड़ा-करकट अनधिकृत कालोनियों से भी निकलता है। इन

अनधिकृत कालोनियों का कूड़ा यहां-वहां डंप होता रहता है और वह शहर को बदसूरत बनाता है। अधिकतर शहरों में अनधिकृत कालोनियों में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है और नियमित कालोनियों का ड्रेनेज सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है।

- यह समझने की जरूरत है कि केवल कचरा एकत्रित करना ही पर्याप्त नहीं है। उसके निस्तारण की भी ठोस व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे तमाम शहरों में पर्याप्त डंपिंग ग्राउंड नहीं हैं। जो हैं वे पहले ही क्षमता से पार हो चुके हैं।
- साफ-सफाई की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों यानी नगर निगमों अथवा नगर पालिकाओं की होती है, लेकिन उनके पास संसाधन सीमित हैं। जहां संसाधन हैं वहां इच्छाशक्ति की कमी है। एक समस्या यह भी है कि स्थानीय निकायों में स्टाफ नहीं बढ़ रहा। कम स्टाफ और सीमित संसाधनों में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती।
- स्वच्छता देश के आर्थिक विकास को भी प्रभावित करती है। औद्योगिक क्षेत्र के आसपास व्यापक स्तर पर होने वाली गंदगी के कारण विदेशी कारोबारी वहां आने में हिचकते हैं ,कुछ तो दोबारा कभी नहीं आते ,दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र में अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिलते है। इसका मतलब है कि औद्योगिक उत्पादन और निर्यात भी स्वच्छता से परोक्ष सरोकार रखता है। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए एक ओर जहां राजनीतिक स्तर पर दृढ़ इच्छाशक्ति आवश्यक है वहीं लोगों की सोच भी बदलनी होगी।

USE PAPER 1/ESSAY/ETHICS

WWW.THECOREIAS.COM

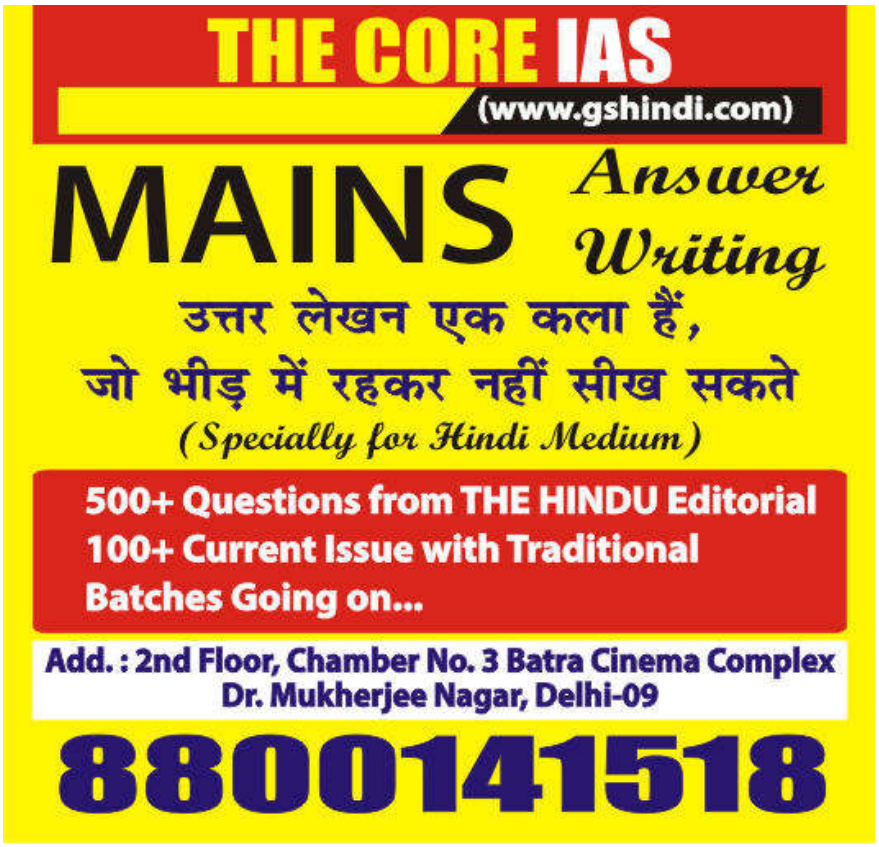

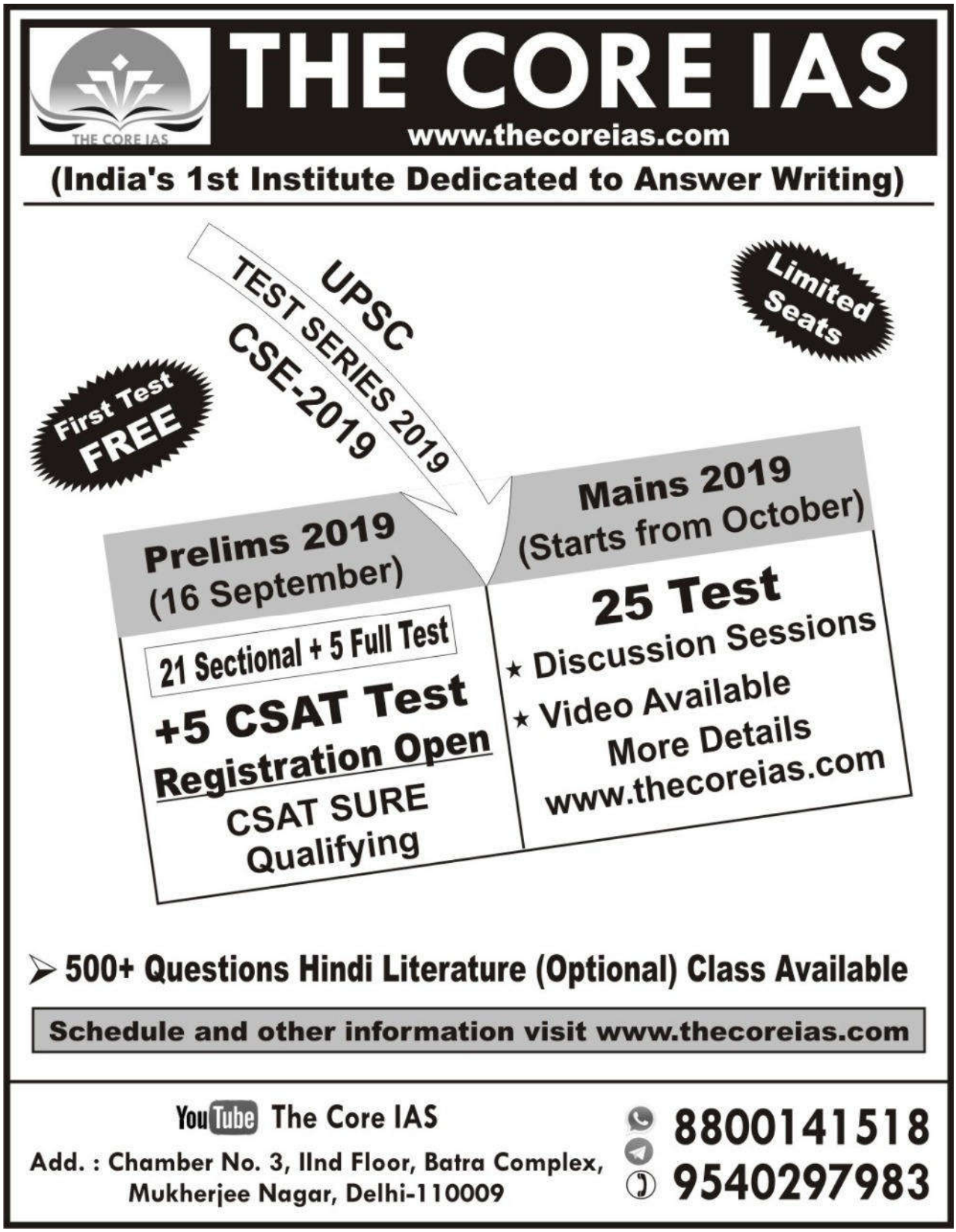
THE CORE IAS
www.thecoreias.com
(India's 1st Institute Dedicated to Answer Writing)
UPSC
TEST SERIES 2019
CSE-2019
First Test FREE
Limited Seats
Prelims 2019
(16 September)
21 Sectional + 5 Full Test
+5 CSAT Test
Registration Open
CSAT SURE
Qualifying
Mains 2019
(Starts from October)
25 Test
★ Discussion Sessions
★ Video Available
More Details
www.thecoreias.com
➢ 500+ Questions Hindi Literature (Optional) Class Available
Schedule and other information visit www.thecoreias.com
YouTube The Core IAS
Add. : Chamber No. 3, IInd Floor, Batra Complex,
Mukherjee Nagar, Delhi-110009
8800141518
9540297983